

//-- सुविवार --//

अकेले हो तो, विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो, तो जुबान पर काबू रखो।

आज

बेबाक

भारतीय लोकतंत्र को जोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता। प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद में धन बल और बाहुबल की बदैलत ऐरे-गैरे-नत्थू खैरे भी पहुंच जाते है और माननीय कहलाते है। लोकसभा में तो खैर योग्य और अयोग्य लोग चुनाव जीतकर जाते है लेकिन संसद का चौर दरवाजा कहे जाने वाले राज्य सभा में पार्टी आला कमान की असीम कृपा से ऐसे लोग पहुंच जाते है जो पंच या पार्षद का भी चुनाव जीतने की योग्यता नहीं रखते। अंधा रेवड़ी बांटगा तो काम के न काज के दुस्मन अनाज के टाइप नकारे लोग माननीय बनते रहेगें।

सूर्योदय
उदय : 5.44 प्रातः
अस्त : 7.05 संध्या
जनसंख्या
विश्व : 7,951,176,790
भारत: 1,406,510,480
बाजार
संसेक्स : 55818.11
निफ्टी : 16628.00
गोल्ड : 51,930 प्रति 10 ग्राम
चांदी : 61,400 प्रति किग्रा
अण्डा दर : 4.66 प्रति नग

आज का दिवस

विश्व साइकिल दिवस

सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता ह। इस दिन को उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समानता और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह दिन अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। सदस्य देशों को क्रॉस-कटिंग विकास रणनीतियों में साइकिल पर विशेष ध्यान देने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने और इसे सतत गतिशीलता और परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना भी है।

बडोदरा की नाइट्रेट फैक्ट्री में ब्लास्ट: प्लांट के 3 बाॅयलर में लगातार 8 धमाके हुए

वडोदर- गुजरात के वडोदरा जिले के नंदेसरी इलाके में दीपक नाइट्रेट नाम की एक कंपनी में गुरुवार दोपहर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद यहां भीषण आग लग गई। हादसे में 15 कर्मचारी घायल हैं। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हादसे के चलते वडोदरा हाईवे बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि

इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई।

बाॅयलर में हुआ था विस्फोट

फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी के अनुसार ब्लास्ट एक बाॅयलर में हुआ था। इसके बाद आग पूरे प्लांट में फैल गई और इसकी चपेट में आकर कई दो अन्य बाॅयलर भी फट गए। लोगों ने बताया कि एक के बाद एक लगातार 8 धमाके सुने गए। इससे पूरे इलाके में हड़कप मच गया।

फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां लगीं

फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण है कि फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई हैं। फिलहाल फैक्ट्री के बाहरी हिस्से की आग पर काबू पा लिया गया है। अभी भी प्लांट के अंदर कई जगह आग धधक रही है।हालात बेकाबू होने के चलते फायर ब्रिगेड टीम ने ब्रिगेड कॉल जारी कर दी है।

गरमा-गरम

हमारी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को जेल में डाल दीजिए-केजरीवाल

जब गैंगस्टर जेल के अंदर से अपना गैंग चला सकते हैं तो हम सरकार क्यों नहीं चला सकते...

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति में युगांतरकारी परिवर्तन करेगी :राज्य मंत्री परमार

गांधीनगर में स्कूली शिक्षा मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में की भागीदारी

भोपाल/नवप्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में “स्कूली शिक्षा मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन- 1 और 2 जून 2022 को हुआ। स्कूली शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा



मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता करने पहुंचे। राज्य मंत्री श्री परमार ने सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अपने

विचार व्यक्त किए। श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करने में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। पाठ्यक्रम में

परिवर्तन, शिक्षा पद्धति में बदलाव, शिक्षकों का प्रशिक्षण सहित अनेक नवाचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्यप्रदेश में किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनते-बदलते-बढ़ते भारत की शिक्षा प्रणाली को नया कलेवर मिल रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति में युगांतरकारी परिवर्तन करेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय कौशल विकास। उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री

राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने विद्या समीक्षा केंद्र, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उत्कृष्टता केंद्र का भ्रमण किया। संस्थानों से जुड़ी विभिन्न जानकारीयों और स्कूली शिक्षा में उपयोगिता को अर्जित किया। राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया सहित इसे राज्यों में लागू करने पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों ने भी सहभागिता की। प्रदेश से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी, **शेष पृष्ठ 7 पर**

दैनिक

आदिवासी तमसः परमस्य

प्रदेश के साथ पूरा देश...

नवप्रदेश

अंदर के पृष्ठों पर

2 | देश-विदेश

4 | अभिव्यक्ति

6 | आंचलिक

7 | आंचलिक

RNI NO.MPHIN/2017/72749

भोपाल, शुक्रवार 3 जून 2022, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत-2079 वर्ष-06 अंक-41 पृष्ठ-08 मूल्य 4 रुपए

भोपाल, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, व रांची से एक साथ प्रकाशित

अब जून-जुलाई में खूब बारिश!

देश के टॉप-10 गर्म शहरों में मप्र के 4 : गर्मी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश में इस साल मई में गर्मी ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भिंड में पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्वालियर, नौगांव, दमोह और खजुराहो भी खूब तपे। देश के टॉप-10 गर्म शहरों में ये 4 शहर मप्रके हैं। भट्टी सा तपने के बाद प्रदेश में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे गर्मी-तपन से कुछ

राहत मिली, लेकिन नौतपा में फिर से गर्मी सताने लगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, मई में 9 एंक्टिव सक्रिय रहे। इस कारण बार-बार मौसम में बदलाव देखने को मिला। जून-जुलाई में खूब बारिश होगी।

ऐसे समझें मप्र में मई के मौसम को



मई की शुरुआत में ही बादल छाए। नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में बूंदबांदी हुई। 8-9 मई को मौसम फिर बदला। गर्मी के साथ लू-तपन का भी असर रहा। रतलाम में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया, जो एमपी में सबसे गर्म रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तापमान 42 डिग्री के पार रहा। 13 मई को प्रदेश **शेष पृष्ठ 7 पर**

देश के रिकॉर्ड में प्रदेश के शहर

20 और 30 मई को प्रदेश के 4 शहर देश में सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। 20 मई को मध्यप्रदेश भट्टी सा तपा। इस कारण प्रदेश के तीन शहर ग्वालियर, खजुराहो, नौगांव और दमोह देश के टॉप-10 गर्म शहरों में शामिल रहे। खजुराहो में 47.2, नौगांव में 47.1 और दमोह में पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दिन भिंड में दिन का पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। भिंड में ऑटोमैटिक वेदर सिस्टम लगा है। इसे अधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता। 30 मई को टॉप-10 शहरों में ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव शामिल रहे।

देश का कानून सबके लिए बराबर किसी को बचाया नहीं जाएगा : भाजपा

नयी दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस मिलने पर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है। जांच एजेंसियां निर्भीकता एवं निष्पक्षता से काम कर रही हैं और किसी को बचाया नहीं जाएगा।

भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति है, भ्रष्टाचार से कतई समझौता नहीं। इस नीति से बड़ा बदलाव भारत में आया है। चाहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) हो या ईडी हो, सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र



रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना काम कर ही है। श्री भाटिया ने कहा कि पिछले आठ साल में देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं। जांच एजेंसियां निर्भीकता एवं निष्पक्षता से अपना दायित्व निभा रही हैं तो भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। देश में एक समय था जब संप्रग के शासनकाल में जांच

और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश का कानून सब पर बराबर लागू होगा। नेशनल हेराल्ड मामले की जानकारी साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या ये सही नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पर एक पैजदारी का मुकदमा धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने को लेकर चल रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं और मांग करते हैं नेशनल हेराल्ड और एजेएल और यंग इंडियन, से जुड़े मामले को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल नामक कंपनी 90 करोड़ रुपये का लोन **शेष पृष्ठ 7 पर**

पंजाब में 420 वीआईपी की सुरक्षा होगी बहाल

● **हाई कोर्ट में फैसले से पलटी भगवंत मान सरकार**



बात कही। इस तरह पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में अपने फैसले से पलटने की बात कही है, जिसके तहत **शेष पृष्ठ 7 पर**

हार्दिक ने पहना केसरिया बाना खुद को बताया मोदी का सिपाही

अहमदाबाद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चर्चित नेता रहे हार्दिक पटेल आज विधिवत सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए।

हार्दिक दोपहर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजधानी गांधीनगर के निकट कोबा स्थित



श्रीकमलम में आधिकारिक रूप से दल में शामिल हुए। वह भाजपा की ओर से ‘विजय मुहूर्त ‘ माने

जाने वाले समय दोपहर 12 बज कर 39 मिनट पर पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने उनके कंधे पर केसरिया अंग वस्त्र रख कर उन्हें विधिवत दल में शामिल किया। आज ही कांग्रेस की महिला नेता श्वेता बट्सभट्ट ने भी केसरिया बाना धारण किया। कभी भाजपा के कट्टर विरोधी रहे हार्दिक ने आज पार्टी और **शेष पृष्ठ 7 पर**

मरीजों को मिलेगी राहत खत्म होगी मनमानी

● **महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच पाएंगे डॉक्टर**

नई दिल्ली । डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में यह प्रावधान किया है। हालांकि, डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। एनएमसी की हाल में जारी

आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते थे और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। सिर्फ उन्ही मरीजों को दवाएं बेच सकते हैं जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का शोषण नहीं हो।

छोटे शहरों में चलन ज्यादा: आजादी से पूर्व बने तमाम कानूनों **शेष पृष्ठ 7 पर**

चीन को घेरने की तैयारी पहली बार 10 आसियान विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा भारत

नई दिल्ली । भारत अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंच का विस्तार करने में जुटा है और इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व तो टक्कर देने के लिए अपनी नीतियों को और मजबूत बना रहा है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़े पैमाने पर घुसपैठ के बीच एक व्यवहार्य भागीदार बनने के लिए भारत 15-17 जून को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रे (आसियान) के सभी 10 देशों के विदेश मंत्रियों की

मेजबानी करेगा।

यह पहला अवसर होगा जब भारत दक्षिण पूर्व एशिया के सभी 10 विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। यह मेजबानी भारत-आसियान साझेदारी के 30 साल और आसियान के साथ 10 साल की रणनीतिक साझेदारी के उपलक्ष्य में हो रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में कनेक्टिविटी, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों के अलावा पिछले सप्ताह

टोक्यो में घोषित इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर चर्चा करने की उम्मीद है। भारत-आसियान साझेदारी के लिए तीन संभावित एरिया स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बताया कि टीके, कुशल और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इन्वैशेन भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच सहयोग दृ **शेष पृष्ठ 7 पर**



आश्रय भी देता है, वृक्ष पृथ्वी को नवजीवन देने का स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर के सर्किट हाउस नं.-1 के परिसर में नीम और बरगद का पौधा लगाने के बाद उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी से अपने जन्म-दिन, विवाह वर्षगांठ और परिजन की पुण्य-स्मृति में

वृक्षारोपण करने का आहवान किया। वृक्षारोपण में जन-अभियान परिपद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जामदार सहित जबलपुर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। आज लगाया गया नीम का पौधा एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर औषधि के रूप में जाना जाता है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष या बड़ भी कहा जाता है।

सोनिया कोरोना संक्रमित

नयी दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और वह फिलहाल किसी से नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। इसी बीच उन्हें हल्का बुखार आया तो उनका कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें वह कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। श्री सुरजेवाला ने कहा कि श्रीमती गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में



आठ जून को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का नोटिस मिला है और वह नोटिस का पालन करते हुए ईडी के सामने पेश होंगी। उन्होंने बताया कि श्रीमती गांधी के स्वास्थ्य को लेकर बराबर जानकारी दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने माली में शांति सैनिकों पर हमले की जांच की मांग की

न्यूरॉक (वार्ता)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने माली अधिकारियों से वहां पर युक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन (एमआइएनयूएसएम) के एक रसद काफ़िले पर बुधवार के हमले की जांच करने और अपराधियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने मांग की है। माली के उत्तरी पूर्वी हिस्से के शहर किडल में कल रसद काफिले पर हुये हमले में एक शांति सैनिक की मौत हो गयी थी। श्री गुटेरेस ने बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को लक्षित कर हमला करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकते हैं। उन्होंने माली के अधिकारियों से इस हमले में शामिल लोगों की पहचान में कोई कसर नहीं छोड़ने का आग्रह किया। इसके अलावा संरा महासचिव ने हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के रिश्तेदारों और जॉर्डन के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने हमले में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। माली में सरकारी सुरक्षा बलों और अलगाववादियों, इस्लामी समूहों के बीच वर्ष 2012 से जारी संघर्ष के एमआइएनयूएसएम 2013 से वहां काम कर रहा है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फैसला लिया था कि माली में राजनीतिक स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है।

देश में 19500 हुए कोरोना के सक्रिय मामले

नई दिल्ली (वार्ता)। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के सक्रिय मामलों में वृद्धि हुयी है। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान 1123 मामले बढ़ने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 19509 हो गयी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि आज सुबह सात बजे तक 193 करोड़ 70 लाख 51 हजार 104 कोविड टीके दिये जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3712 नये मरीज सामने आये हैं। इनके साथ ही देश में कोरोना रोगियों की संख्या 19 हजार 509 हो गयी है।

यह संक्रमित मामलों का 0.05 प्रतिशत है। दैनिक संक्रमण दर 0.84 प्रतिशत हो गयी है। मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में 2584 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं। अभी तक कुल चार करोड़ 26 लाख 20 हजार 394 कोविड से उन्नर चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है। देश में पिछले 24 घटे में 4 लाख 41 हजार 989 कोविड परीक्षण किए गये हैं। देश में कुल

85 करोड़ 13 लाख 38 हजार 595 कोविड परीक्षण किए हैं। वहीं देश में इस जानलेवा विषाणु के कारण पांच लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 524641 हो गये।
महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 557 बढ़कर 4032 हो गई है। वहीं, 524 और लोगों के स्वस्थ होने के बाद इससे निजात पाने वाले लोगों का आंकड़ा 7736275 तक पहुंच गया है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,47,860 हो गया है।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी मुश्किल

नई दिल्ली (वार्ता)। राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के आरोपों से वि्री कांग्रेस अपनों के विरोध तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रणनीति के कारण कई सीटों पर फंसी हुई नजर आ रही है और राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हरियाणा में एक सीट पर उसकी मुश्किल ज्यादा ही बढ़ गई है। राज्य सभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान किया है उसको लेकर पार्टी में शुरू से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विरोध श्री इमरान प्रतापगढ़ी का हो रहा है। कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र से टिकट दिया है। उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कड़ा पत्र लिखकर पृष्ठ रहे हैं कि क्या इसी तरह से दरबारियों को टिकट दिया जाता रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और नगमा प्रतागढ़ी भी श्री प्रतापगढ़ी को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। श्री खेड़ा ने कहा कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई।

श्रीलंका में भारी बारिश से एक की मौत

कोलंबो (वार्ता)। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि गुरुवार सुबह देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान से 12,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और इसके साथ एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश से प्रभावित लोग रत्नापुरा, कैंडी, कालुतारा, गम्पहा, कोलंबो और मतारा जिलों के 2,672 परिवारों के हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के सहायक निदेशक प्रदीप कोर्डीपिली ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गम्पहा है, जहां 2,448 परिवारों के 8,517 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतक एक आपदा राहत अधिकारी था, जिसकी तेज धाराओं में बह जाने से मृत्यु हो गई। पिछले एक सप्ताह में इस दक्षिण एशियाई देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की सूचना है। मौसम विभाग ने घोषणा की कि देश में इस सप्ताह के दौरान बारिश या गज के साथ बौछारें पड़ेंगी और चेतावनी दी कि बाढ़ का खतरा जारी रहेगा।

चीन में भूस्खलन में दो की मौत

चांगशा (वार्ता / शिन्हुआ)। चीन के मध्यवर्ती हुनान प्रांत के हुआईहुआ शहर में गुरुवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लापता हैं। मायांग मिशओ ऑटोनोंमस काउंटी के तोंगलिंगशी गांव में गुरुवार तड़के करीब तीन बजे एक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से दो घर गिर गए और चार लोग लापता हो गए। दूसरा भूस्खलन काउंटी के दाहुपिंग गांव में सुबह करीब 4 बजे हुआ, जिसमें दो पीड़ितों की मौत हो गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में बचावकर्मী एकत्र हैं और बचाव कार्य अभी भी जारी है।

ब्रिटेन यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजेगा

लंदन (वार्ता)। ब्रिटेन यूक्रेन को रूस के खिलाफलड़ने में मदद के लिए मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजेगा। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वालेस ने कहा कि यूक्रेनी सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वह 80 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाले एम 270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजेगा। जिससे यूक्रेनी सेना की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। रक्षा सचिव ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर उसने महत्वपूर्ण हथियारों की आपूर्ति करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को यूक्रेन को हाई मॉबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (एचआईएमएआरएस) देने के अमेरिका के फैसले का साथ देने के रूप में बताया है।

ब्राजील में बारिश से अब तक 107 की हुई मौत

रिया डि जनेरियो (वार्ता/शिन्हुआ)। ब्राजील के पूर्वोत्तर परनम्बुको राज्य में भारी बरसात से मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है तथा 11 लोग अभी तक लापता हैं। राज्य सरकार के अनुसार भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा 6650 लोग बेघर हुए हैं। बरसात से ज्यादातर मौतें राज्य की राजधानी रिसिफ और उसके महानगरीय क्षेत्रों में हुई हैं। परनम्बुको के इतिहास में मई 1966 में आई बाढ़ में 175 लोगों की मौत के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है। दमकलकर्मी और ब्राजील की सेना प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से लापता लोगों के शवों की तलाश कर रही है। परनम्बुको की 24 नगर पालिकाओं ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।

जागिड़, संतोष

कैप्टन जैक स्पैरो ने जीता केस, पूर्व पत्नी को देना होगा 1 करोड़ 50 लाख डॉलर का मुआवजा

अमेरिका का चर्चित केस, टीवी पर होता था लाइव टेलीकास्ट



कोर्ट ने जॉनी डेप को भी माना दोषी-

जूरी ने एंबरहर्ड का पक्ष भी सुना,जिसमें कहा गया कि डेप

ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के मामले में दिल्ली देश को दिखा रही रास्ता : केजरीवाल

दिल्ली को देख अब दूसरे राज्य भी इसे शुरू करने की राह में

नई दिल्ली ।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सराय काले खां स्थित आरटीओ दफ्तर का दौरा कर ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक का जायजा लिया और कहा कि फेसलेस सर्विसेज और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के मामले में राजधानी पूरे देश को रास्ता दिखा रही है।

श्री केजरीवाल ने कहा कि देश में फेसलेस सुविधा शुरू करने वाला दिल्ली पहला और अकेला राज्य है। पिछले साल हमने परिवहन विभाग में यह सुविधा शुरू की। पहले यहां रोज़ दो हजार लोग आते थे और अब केवल 100 से भी कम लोग आते हैं। अब घर बैठे सबका काम होता है और रिश्तख़ोरो बिन्कुलु बंद हो गई। पिछले नौ-10 महीने में करीब 16 लाख दिल्लीवासी फेसलेस सर्विस को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे सब लोग ऑनलाइन सारे काम करा सकते हैं। उसके बाद, अगस्त के महीने में इसको पूरे दिल्ली में लागू किया गया और हमने प्रतिकात्मक रूप से एक दफ्तर पर ताला लगा दिया था। अब दफ्तरों के अंदर लोगों को आने की



लोगों की सहूलियत के लिए सिस्टम बनाते जा रहे हैं। दिल्ली को देख अब दूसरे राज्य भी इसे शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फवरी के महीने में पायलट आधार पर फ़ेसलेस सर्विस शुरू की थी। फ़ेसलेस सर्विस का मतलब कि किसी को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे सब लोग ऑनलाइन सारे काम करा सकते हैं। उसके बाद, अगस्त के महीने में इसको पूरे दिल्ली में लागू किया गया और हमने प्रतिकात्मक रूप से एक दफ्तर पर ताला लगा दिया था। अब दफ्तरों के अंदर लोगों को आने की

अफगानिस्तान के दौरे पर विदेश मंत्रालय का दल

नई दिल्ली (वार्ता)।भारत का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अफ़ग़ानिस्तान की यात्रा पर गया है, जहां वह सभी वर्गों के स्थानीय लोगों को मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अलावा तालिबान के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगा। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान एवं ईरान डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव जे. पी. सिंह की अगुवाई में काबुल में भारत से आने वाली मानवीय सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था का जायजा लेने गया है। विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल अफ़ग़ानिस्तान में मानवीय सहायता के वितरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और देश में भारतीय सहायता से चल रही परियोजनाओं के

कार्यान्वयन स्थलों का दौरा भी करेगा। उल्लेखनीय है कि अफ़ग़ान लोगों की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत ने सहायता देने का फैसला किया था। इस ऋम में भारत सरकार करीब 20 हजार टन गेहूँ, 13 टन दवाइयां, पांच लाख डोज़ू कोविड वैक्सोन और सर्दियों के कपड़े अफ़ग़ानिस्तान भेजे हैं। यह सामग्री काबुल स्थित इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम को सौंपी गई थी। इसके अलावा भी भारत और भी चिकित्सीय एवं खाद्य सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत ने ईरान में रह रहे अफ़ग़ान शरणार्थियों के लिए भारत निर्मित कोवैक्सिन के 10 लाख डोज़, 6 करोड़ पोलियो वैक्सिन और दो टन आवश्यक दवाएं भेंट की थी। भारत की अफ़ग़ानिस्तान के लोगों

विस्तारा के पायलट ने ‘बिना ट्रेनिंग’ के लैंड किया विमान, एयरलाइन पर लगा 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। भारत के विमानन नियामक ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए एयर विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विस्तारा एयरलाइन पर एक अनुचित रूप से प्रशिक्षित पायलट को मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डे पर पर विमान उतारने की अनुमति देने के लिए जुर्माना लगाया है।

अधिकारियों ने कहा कि पायलट, जो फ्लाइट का फर्ट ऑफ़िसर था उसने हाल ही में एक सिम्युलेटर में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाई अड्डे पर उतारा। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर उल्लंघन था जिससे



विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। हालांकि यह अभी साफ़नहीं हो पाया है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी। किसी उड़ान के प्रथम



के वकील ने उन्हें बदनाम किया था और उनके दुर्व्यवहार के आरोपों को धोखा कहा था। जूरी सदस्यों ने कहा कि डेप को

क्या है मामला

डेप ने दिसंबर 2018 के ऑप-एड में फेयरफैक्स काउंटी सर्किट अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। दरअसल हर्ड ने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था और उसने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसे लेकर ही जॉनी डेप अदालत चले गए थे और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद यह फैसला सुनाया। जॉनी डेप को पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड 1 करोड़ 50 लाख डॉलर की बड़ी रकम अदा करनी होगी। मानहानि के केस में पूर्व दंपति ने एक-दूसरे पर हिसा का आरोप लगाया था। यह दुनिया का संगवतः पहला ऐसा मामला है,जब पूर्व पत्नी को अपने पूर्व पति को इतनी बड़ी रकम अदा करेगी। वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी सर्किट कोर्ट में यह फैसला बुधवार दोपहर को सुनाया गया। हर्ड ने दावा किया था कि डेप ने अपनी शादी से पहले और बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।हर्ड के आरोपों को गलत बताते हुए जॉनी डेप ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था।

हज़ार्ने के रूप में एक करोड़ 50 लाख डॉलर का भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि हर्ड को 20 लाख डॉलर मिलने चाहिए।

यानी कोर्ट ने जॉनी डेप को भी पूरे मामले में दोषी माना है। अमेरिका में यह केस चर्चित रहा।इस बात का अंदाजा

सिद्ध मूसेवाला हत्याकांड परिवार ने उठाई एनआईए या सीबीआई जांच की मांग



चंडीगढ़। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने हत्या के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने गृहमंत्रालय को पत्र भेजा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दी है। उन्होंने गुरुवार को मूसेवाला के पिता से मुलाकात की है। गायक की रविवार को जवाहर के गांव में हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। शेखावत ने बताया कि आपकों रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा और आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। पहले इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था। हमारी ईमानदार सरकार है। इसी वजह से एक-एक करके लोगों की सहूलियत के लिए हम सिस्टम बनाते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सराय काले खां दिल्ली का सबसे पहला

गायक की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

बुधवार को पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंघा की अगुवाई में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की थी। पार्टी ने पुरोहित को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही नेताओं ने मूसेवाला की मौत के कत्ल की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंघा ने किया। अन्य सदस्यों में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पार्टी को राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु, राजकुमार चब्बेवाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा और बलबीर सिंह सिद्धू आदि शामिल थे।

नेशनल हेराल्ड : विदेश दौरे पर राहुल , 5 जून को वापसी , ईडी से मांगेंगे दूसरी तारीख

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी को तलब किया है। इसी बीच खबर है कि राहुल बीते करीब 12 दिनों से विदेश दौरे पर हैं और 5 जून को भारत लौटेंगे। कहा जा रहा है कि वापसी पर वह ईडी से पूछताछ के लिए दूसरी तारीख की मांग कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।

सूत्रों के हवाले से लिखा कि विदेश दौरे पर गए राहुल 5 जून को भार लौट सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों ने एजेंसी को बताया, ‘राहुल गांधी ने लंदन 20 से 23 मई के बीच आयोजित कार्यक्रम में देश छोड़ दिया था। इसके बाद से ही वह भारत नहीं लौटे हैं।’ हाल ही में कांग्रेस नेता ने कैब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा, ‘राहुल गांधी के 5 जून तक वापस आ सकते हैं, जिसके बाद वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी से दूसरी तारीख की मांग करेंगे।’ पार्टी सूत्रों



ने कहा कि सोनिया को 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। वहीं, राहुल को 2 जून को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन पृथ्वी सेई कांग्रेस अध्यक्ष ने दूष में नहीं होने के चलते 5 जून के बाद समय मांगा है।

पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ‘दोनों नेता ईडी के सामने पेश होंगे... हम उनका सामना करेंगे। हम ऐसी चालबाजियों से जरा भी डरे नहीं हैं।’ उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। दोनों प्रवक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि जब भी ईडी चाहेंगे, दोनों नेता पेश हो जाएंगे।

गेहूं की कालाबाजारी पर खामोश है सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि देश में बड़े स्तर पर गेहूँ की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आदि में गेहूँ की खरीद नहीं हो रही है और इसकी जमाखोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद में जमाखोरी और कालाबाजारी साफ़ है। उत्तरप्रदेश में गेहूँ खरीद लक्ष्य 60 लाख टन का, लेकिन खरीद 2.93 लाख टन की गई है। इसी तरह से बिहार में गेहूँ खरीद लक्ष्य 10 लाख टन का है लेकिन खरीद 3.521 टन की गई। उत्तराखंड में



गेहूँ खरीद लक्ष्य 22 लाख टन, लेकिन खरीद मात्र 20 हजार टन हुई। प्रवक्ता ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि गेहूँ खरीद में जमाखोरी और कालाबाजारी कर कितने लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है तो जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के खिलाफकार्रवाई तथा छापेमारी क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने इसे गरीब-मध्यम वर्ग पर बतौर हमला करार देते हुए कहा कि वे अब महंगा गेहूँ खरीदने को मजबूर होंगे।

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

संपादकीय



भ्रष्ट मंत्री का बचाव आखिर क्यों?

नई दिल्ली की केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने दस दिनों के लिए हिरासत में लिया है। जाहिर है ईंडी के पास सतेन्द्र जैने के खिलाफ पुख्ता प्रमाण हैं तभी उसे दस दिन की हिरासत में रखा गया है। उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में और कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ईंडी की इस कार्यवाही को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताते हुए नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भ्रष्ट मंत्री सतेन्द्र जैन का बचाव करते हुए उन्हें कट्टर ईमानदार नेता बताया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले से जुड़े तमाम कागजात देखों हैं और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सतेन्द्र जैन के खिलाफ फर्जी मामला बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल शायद यह भूल रहे हैं कि वे एक मुख्यमंत्री हैं कोई न्यायाधीश नहीं है जो किसी भी आरोपी को निर्दोष करार दे दें। यदि वास्तव में सतेन्द्र जैन कट्टर ईमानदार है तो न्यायालय उन्हें वैसे ही निर्दोष बरी कर देगा लेकिन जब तक ईंडी की जांच चल रही है और मामला अदालत में नहीं पहुंच जाता तब तक अरविंद केजरीवाल को आरोपी मंत्री का बचाव नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस दिन वे न्यायालय से बेदाग बरी हो जाएंगे उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। यदि आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार बताती है तो उसे भ्रष्टाचार के आरोपियों का बचाव नहीं करना चाहिए। यदि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो साफ जाहिर है कि न सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी दाल काली है। नई दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी जांच की तलवार लटक रही है। जाहिर है आगे चलकर नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। यह वजह है कि ईंडी की कार्यवाही से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है और वे इस कार्यवाही को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वह राजनीतिक बदला लेने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यदि ऐसा है तो इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वे इस मामले को न्यायालय में ले जाएं जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल द्वारा मंगलवार को दिए गए उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार, देश से ‘‘गद्दारी’’ के समान है और पूछा कि ऐसे में फिर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एक ‘‘गद्दार’’ का बचाव क्यों कर रहे हैं, जिसने कथित तौर पर सरकारी खजाने और जनता के साथ धोखा किया है? जैन के खिलाफ आरोपों की झड़ियां लगाते हुए ईरानी ने केजरीवाल से कई सवाल भी किए और पूछा कि वह बताएं कि क्या ये आरोप सही हैं या नहीं।

विचार

दुशाबे में पाक क्यों नहीं आया?



डॉ. वेदप्रसाद वैदिक

अफ़ग़ानिस्तान के आठ पड़ोसी देशों का एक चौथा सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशाबे में इस हफ्ते हुआ। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गीजिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तो भाग लिया ही, उनके साथ रूस, चीन, ईरान और भारत के प्रतिनिधि भी उसमें गए थे। यह सम्मेलन इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का था। भारत से हमारे प्रतिनिधि अजित दोभाल थे। उनके साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जे.पी. सिंह भी थे लेकिन पिछली बार जब यह सम्मेलन भारत में हुआ था तो चीनी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने कोई बहाना बना दिया था। पाकिस्तान ने तो उस सम्मेलन में आया था और न ही इस सम्मेलन में आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो इसमें भारत की उपस्थिति ऐसी है, जैसे किसी झड़ंग रूम में हाथी की होती है। भारत इन देशों में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के लिए वह सिर्फ दं बन सकता है लेकिन इस बार चीन दुशाबे में तो आया लेकिन दिल्ली में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वह दिल्ली आता तो पाकिस्तान नाराज हो सकता था। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मामूली नहीं है। इसप्ती है। इसके बावजूद भारत और ताजिकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों की भर्त्सना की और काबुल में सर्वसमावेशी सरकार की मांग की। ताजिकिस्तान वही देश है, जहां काबुल से भागकर राष्ट्रपति अशरफगनी पहुंच गए थे। अफ़ग़ानिस्तान के फरसीभाषी ताजिक लोग उसका सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं जबकि तालिबान मुख्यतः गिलज़ई पठान हैं। ताजिकिस्तान में बैठकर ही अहमदशाह मसूद ने काबुल की रूसपरस्त सत्ता को हिला रखा था। अब भी तालिबान का काबुल पर कब्जा होते ही मसूद के बेटे और भाई दुशाबे में बैठकर तथाकथित प्रवासी सरकार चला रहे हैं। इस सम्मेलन से तालिबान इसलिए भी बाहर है कि एक तो उनकी सरकार को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है और दूसरा वे ताजिक दखलतंजों के खिलाफ हैं। चाहे जो हो, इस सम्मेलन में रूस और चीन की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन का रूस अब ब्रेजेनवैफ वाला रूस नहीं रहा और चीन को अपने शिन च्यांग में चल रहे उखर मुसलमानों से बहुत परेशानी है। लाखों उखर मुसलमानों को चीन ने यातना-शिविरों में बंद कर रखा है। इस दृष्टि से भारत और चीन की चिंताएं लगभग एक-जैसी हैं। जैसे हमारे कश्मीर और पंजाब में वैसे ही शिनच्यांग में आतंकवादी काभी सक्रिय हैं। पाकिस्तान को इस सम्मेलन में सबसे अधिक सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद सबसे ज्यादा उसी का नुकसान कर रहा है। इस सम्मेलन ने आतंकवाद-विरोध और सर्वसमावेशी सरकार की जमकर मांग की लेकिन मंहंगई, बेरोजगारी और अभाव से ग्रस्त जनता की मदद के लिए ये सभी राष्ट्र कोई बड़ी घोषणा करते तो बहुत अच्छा रहता।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

सुरज मत छू



सुरज मत छू उंगलियां जल जाएंगी। चाँद पकड़ना मत मुड़ियाँ जम जाएंगी। रात बहुत हुआ अब सो जा, तारों से तो खेले मत, हथेलियों छिल जाएंगी। परेशान हूँ मैं तेरी शराबतों से, और समंदर मत ला देहरी पर, घड़े सब भरे पड़े हैं नमकीन पानी से। बस एक लोटकी पोखर का पानी भर ला, नहीं तो प्यासे मर जाएँगे।

- राकेश मिश्रा

पथ दुर्गम अंधकार



पथ दुर्गम अंधकार दुकर प्रवाह जुगनु सम प्रकाश अंतर मन जागे आस जागे उड़ेग जागे संत्रास मन रे घर धीर अंजानी पीड़गंतव्य की ओर बस दो कदम और जीवन संग्राम जूड़े इसान प्राणों का मोह मृत्यू से भय लोभ और त्याग मानव स्वभाव जय या पराजय संसय आघाध ममता की आस नफ़्त की आग गंतव्य की ओर बस दो कदम और। - शिखा लाहिरी

खास पत्नी



हवाएं ओस से भीगीं तराने प्यार के गायें पहाड़ों गीत गाओ तुम , महकते फूल मुस्कayne नदी छनका रही पायल , बहकती आम की डाली सखी कैसे कहूँ अब मैं , पिया जी ख्वाब में आये घने कुतल सँवारे थे , सजी सँवरी निहाळ पथनीहँ लगता सखी मन अब , सँदेसा काग से पाये बहारों में भी खुशबू थी, चमन करते इशारे थे कभी तो सिर्फउनकी है , तलैया ताल हवाये सुधा रस प्रेम का बरसा , पपीहे सी पुकारूँ मैं धरा सी ज्योति प्यासी है , तभी वो मेघ बन छाये। - ज्योत्सना सक्सेना

जानें कैसे कैसे मरीज बैठे हैं कोई

जानें कैसे कैसे मरीज बैठे हैं कोई वफ़ में जख़्म ,तो कोई दिल की टूटी तस्बीर ले के बैठे है , न तो किसी को मर्ज़ पता है ,न तो हाकिम का पता पता है , वक़ से मरहम को उम्मीद लिए बैठे है , जाने कैसे कैसे मरीज बैठे हैं कोई टूटते रिस्तो की साँस सँभाले ,तो कोई अपनी ही कमियों की गर्म तासीर ले के बैठे है , न तो किसी को नब्ब पता है ,न ही ठंडी हवा का रुख पता है , जाने कैसे कैसे मरीज बैठे हैं कोई तन्हाई के अवसाद ,तो कोई भीड़ का झुझलापन ले के बैठे है , न तो किसी को अपने मिजाज की महफ़िल पता है ,न तो किसी को सुकून की जगह का पता पता है जाने कैसे कैसे मरीज बैठे हैं।

- नमन कुमार मिश्रा

शुभ भाव परिचायक जय जय

शुभ भाव परिचायक जय जय, भारत जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय।- वर्षा वर्धिता श्रीवास्तव

श्री अर्जुन गुंडा

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री

देश में अनुसूचित जाति के व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा, 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को नीति आयोग द्वारा आदिवासी विकास के लिए हर साल उनके कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत की सीमा में अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2013-2014 में अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) का कुल बजट परिव्यय 21,525.36 करोड़ रुपये था जो की वर्ष 2021-22 में बढ़कर 85,930.47 करोड़ रुपये हो गया है। जनजातीय समाज के समुद्र संचुकीत विरासत एवं महत्व को संजोने का कार्य हमारे देश भर में स्थित 27 जनजातीय शोध संस्थान कर रहे हैं। यह संस्थान जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, साहित्य के संरक्षण और उनके प्रचार की दिशा में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरा हमेशा से यह मानना है कि आदिवासियों के विकास मार्ग को प्रशस्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा।

ओ पी गुप्ता

आलोचकों ने किसानों के लिए बेहतर कीमतों का दावा भी उठाया है। तथ्य यह है कि हर साल लगभग पूरी खरीद गई के मध्य तक पूरी हो जाती है। इस साल, किसानों ने अपने लगाना पूरे उत्पादन के लिए अधिक कीमत का आनंद लिया है। सरकार ने अभी भी राश्यों को गई के अंत तक गेहूँ खरीदने की सलाह दी है। गेहूँ के व्यापार ने हमारी जोर पर अक्षर डाला है, जिससे आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है। इससे निपटने में, विमान में यात्रियों को दी जाने वाली सलाह सटीक बैठती है: आपात स्थिति के मामले में, दूसरों की मदद करने से पहले, अपना स्वयं का अतिरिक्तना ग्राहक पसना। एक दुर्घटना लैंडिंग के लिए, 7-7 और IMF को अपने दिशाओं को छेड़ना चाहिए और रूसी और यूक्रेनी गेहूँ के मुक्त मार्ग के लिए पिव बनानी चाहिए अथवा विश्व व्यापार संगठन से भारत को सरकारी खजाने से गेहूँ का निर्यात करने का आग्रह करना चाहिए।

अभिव्यक्ति

सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण

सन् 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते समय कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है।

प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय योजना को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार मौलिक और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान जनहित और देशहित के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

यदि हम इक्कीसवीं सदी के सुनहरे भारत का सपना देखते हैं, तो जनजातीय समाज का व्यापक विकास एवं उनके जीवन-स्तर में सुधार और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे कोई भी समाज, वर्ग और राष्ट्र सकारात्मक दिशा में अग्रसित होकर भविष्य की एक समृद्धशाली संकल्पना को साकार कर सकता है।

मुझे आप सब से साझा करते हुए प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति है कि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है, प्री-पोस्ट मैट्रिक, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, छात्रों को पाठ्यक्रम की अवधि के लिए संपूर्ण शुल्क के साथ-साथ भत्ता भी प्रदान किया जाता है। उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के तहत आईआईटी, आईआईएम, एम्स आदि जैसे उच्च श्रेणी के संस्थानों में प्रवेश लेने वाले 1000 छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में देश के अन्य शहरों या विदेश में जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले होनहार जनजातीय विद्यार्थियों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की

जाती है। जहाँ वर्ष 2014-15 में यह राशि 978 करोड़ रुपये थी वहीं वर्ष 2021-22 में यह राशि 2546 करोड़ रुपये हो गयी है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 32 लाख से अधिक जनजातीय छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंच रहा है।

देश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण



शिक्षा प्रदान करने के साथ उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास है की इन विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात विद्यार्थीगण भविष्य में एक नए भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2013-14 में जहाँ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का बजट परिव्यय 278.76 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2021-22 में यह अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 1418 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2013-14 तक 167 स्वीकृत विद्यालय थे जो वर्ष 2021-22 तक बढ़कर 679 हो गए हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की लागत वर्ष 2013-14 में 12 करोड़ रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 16 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अब 38 करोड़ रुपये एवं 48 करोड़ रुपये कर दी गयी है। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय दूरस्थ और दुर्लभ आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए

स्वैच्छक संगठनों (वीओ))/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से सरकारी प्रयासों को पूरक करने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के चयन से लेकर अनुदान के उपयोग तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए एक पारदर्शी प्रणाली बनाई है।

देश में अनुसूचित जाति के त्वरित

प्रशस्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) द्वारा किया गया अनुसंधान हमारे आदिवासी विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का आधार बन रहे हैं। 15 अगस्त, 2016 को देश के स्वतंत्रता दिवस पर अपने सम्पाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम आदिवासी नायकों के योगदान को जन-जन में उजागर करने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना देश के विभिन्न राज्यों में करने की उद्घोषणा की थी ताकि हमारी भावी पीढ़ी अपने गौरवपूर्ण अतीत से परिचित हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाये हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में स्थित दस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली

‘जनजातीय गौरव दिवस’ पर 15 नवंबर, 2021 को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया था।

सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण- के लिए विगत 8 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए उक्त कार्य जहां एक ओर सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हैं, वहीं दूसरी ओर यह हमारी सरकार के दूरदर्शिता को भी स्पष्ट करते हैं। निकट भविष्य में ही इन प्रयासों के और सुफल हमें देखने को मिलेंगे। जनजातीय समाज की देश हित में एक निश्चित भूमिका है और यह वही इसे बखूबी निभा रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर हमारा यह ध्येय है कि आदिवासी समाज जो उन्नति तथा विकास के सुअवसर लगातार प्राप्त हो। निकट भविष्य में हमारा यह प्रयास जनजातीय समाज के लिए एक वरदान साबित होगा।

गेहूं निर्यात पर हमारी आलोचना

पिछले महीने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक गंभीर चेतावनी जारी की थी कि वैश्विक खाद्य कीमतों में +अत्याधुनिक+ वृद्धि हो सकती है। भारत सहित दुनिया भर में फसलों पर खराब मौसम की भार पड़ने की खबरें आ रही थी, और कुछ विश्लेषकों का अनुमान था कि दुनिया में गेहूं का स्टॉक कम है।

इस संदर्भ में, चीनी और गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित और विनियमित करने का भारत का निर्णय प्रशंसनीय कदम है जो हमारे अपने 130 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर शुल्क में कटौती, ईंधन पर कर में कटौती और स्टील पर निर्यात शुल्क उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं - भारतीयों के हितों की रक्षा करना ठीक ऐसा है जैसे विकसित राष्ट्र पहले अपने नागरिकों के कल्याण की देखभाल करते हैं।

2021-22 में भारत ने लगभग 105 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया और 7 मीट्रिक टन का निर्यात किया। इस वर्ष, गेहूं उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 111.32 मीट्रिक टन था जब हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को खिलाने के लिए अधिक गेहूं निर्यात करने की पेशकश की थी, लेकिन हाल के महीनों में असामान्य रूप से गर्मी बढ़ने के कारण ये अनुमान घटकर 105 मीट्रिक टन रह गया। 13 मई से निर्यात प्रतिबंधों के बाद कीमतों में वृद्धि बंद हो गई और हाल के दिनों में इसमें गिरावट आई है। इसी तरह, चीनी पर प्रतिबंध से यह सुनिश्चित होगा कि देश में पर्याप्त स्टॉक है और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

सोयन हैं चौकाने वाली बात है कि विकसित देशों ने भारत को अलग कर दिया और गेहूं के निर्यात पर हमारे फैसले की आलोचना की, जैसे कि हम पारंपरिक रूप से दुनिया के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे हैं और इस दुनिया की खाद्य सुरक्षा नई

दिल्ली से बनी नीतियों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की मांग की। सच तो यह है कि गेहूं निर्यातक देशों में भारत



2020 में 19वें, 2019 में 35वें, 2018 में 36वें, 2017 में 36वें और 2016 में 37वें स्थान पर रहा। वैश्विक गेहूं व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम रही है।

भारत की आलोचना करने वाले देशों के जी-7 समूह को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे डेटा का उपयोग करके ये तय करें कि दोषी किसे ठहराया जाना चाहिए। 2020 में वैश्विक गेहूं व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की हिस्सेदारी 13व थी, जबकि फ्रांस और यूक्रेन प्रत्येक की हिस्सेदारी 10व थी। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना प्रत्येक को 5व पर आँका गया। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात बढ़ा, लेकिन वे इन देशों के शिपमेंट की तुलना में बहुत कम थे।

रूस की हिस्सेदारी 19व है। इसे यूक्रेन के गेहूं में जोड़ें और ये हम एक चौथाई से अधिक वैश्विक आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो बाधित नहीं होगा अगर वैश्विक खाद्य

सुरक्षा के स्व-घोषित चैंपियन ने व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया होता। आज रूस व्यापार प्रतिबंधों के कारण गेहूं का निर्यात करने में असमर्थ है। दुख की बात है कि ये यूरोप द्वारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात पर लागू नहीं होता। आपूर्ति के एक प्रमुख स्रोत को बाधित करने के बाद, भारत पर हमला करना गलत है।

इजिप्ट, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, कोसोवो, बेलारूस ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इजिप्ट और तुर्की भी भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खुद निर्यात की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के देश खाना पकाने के तेल, तिलहन, मवेशी, जई, आलू, चीनी, अनाज, मांस, आटा, मुर्गी पालन, अंडे, पास्ता, प्रसंस्कृत भोजन, चिकन मांस, चावल, मक्का, सोयाबीन आदि पर निर्यात

नियंत्रण के साथ अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, कैमरून, कुवैत, हंगरी, घाना, अल्जीरिया, मोरocco जैसे कई देशों ने खाद्य निर्यात पर पाबन्दी लगा दी है। पाम तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध ने बाजार को हिलकर रख दिया क्योंकि देश में सभी वनस्पति तेल निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। इस प्रतिबंध का भारत और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जो खाना पकाने के तेल के लिए इंडोनेशिया पर बहुत अधिक निर्भर हैं। विकसित दुनिया या आईएमएफ को इसकी परवाह नहीं है। दिखावा करने वाले व्यक्ति को भी खाना बर्बाद नहीं करना सीखना होगा। घरेलू खाद्य अपव्यय पर हृक्षत्र खाद्य सूचकांक 2021 के अनुसार, भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक है। हमारा अनुमानित अपव्यय 50 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है।

QUIZ TIME

- सियांग नदी, जो लाल पांडा प्रजाति के संदर्भ में चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है?
- रुकेसिया नाना, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस परिवार की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है?
- प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है?
- किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी दीप-नारकोडम दीप में पहली बार सफेद दांतों वाली धूसर प्रजाति की खोज की गई है?
- इंडोनेशिया में 170 साल बाद किस पक्षी को देखा गया है?

1. अरुणाचल प्रदेश (A) और 2. उत्तराखण्ड (B) 3. मेघालय (C) 4. मिज़ोरम (D) 5. आंध्र प्रदेश (E) 6. तमिलनाडु (F) 7. कर्नाटक (G) 8. गुजरात (H) 9. राजस्थान (I) 10. महाराष्ट्र (J)

आज का इतिहास

नई दिल्ली 11867: भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरिवंशदास शास्त्री का जन्म। 1901: ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप का जन्म। 1915: ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार की उपाधि से नवाजा। 1918: महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हिन्दी राजभाषा मानी गई। 1924: तमिलनाडु के पांच बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का जन्म। 1930: भारत में ऐतिहासिक रेल हड़ताल कराने वाले और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फोर्नाडिस का जन्म। 1943: संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की। 1947: ब्रिटिश राज में भारत के

आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया। 1959: सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया। 1972: देश के पहले आधुनिक युद्ध पोत नीलगिरी को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावतरित किया। 1974: बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन। 1985: भारत सरकार ने पांच दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया। 1999: होवरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक क्रिस्टोफ़र काकरैल का निधन। 2004: केन फेर्ड 2004 में नासा के अंतरिक्ष खोज पेलन के नेतृत्वकर्ता बने। 2005: फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया। 2014: तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन।

- सीमा राय द्विवेदी

आचार संहिता लगते ही नगर पंचायत कर्मचारियों ने हटाए राजनीतिक दलों के बैनर- पोस्टर

नगरीय निकाय चुनाव ने बढ़ा दिया राजनीतिक पारा, दावेदार हुए सक्रिय, आचार संहिता का पालन कराने मुस्तैद प्रशासन

सोहागपुर/ नवप्रदेश।। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा पूर्व में हो चुकी है। अब नगरी निकाय के चुनाव की घोषणा होते ही तपती गर्मी में राजनीतिक तापमान का पारा बढ़ गया चौक चौराहे चाय पान दुकानों पर संभावित प्रत्याशियों की चर्चाएं हो रही है अच्छे बुरे और ईमानदार का तगमा समर्थक दे रहे हैं साथ ही इस बार चुनाव में फला को देखना है सबक सिखाना यह भी चर्चा आम है नगर परिषद सोहागपुर का चुनाव 6 जुलाई को होगा महिला अध्यक्ष के लिए सीट आरक्षित है जिससे संभावित प्रबल दावेदार पिछड़ा वर्ग के पुरुष प्रत्याशी परेशान है तथा सुरक्षित सीट की तलाश में है राजनीति में भविष्य सवारने की इच्छा रखते हुए दोनों ही दल के प्रत्याशी समर्थकों के साथ गहन मंथन में लगे अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों से होगा अर्थात अध्यक्ष बनने के लिए पार्षद बनना आवश्यक है भाजपा से अनिल गहरेया, संजय मालवीय प्रशांत मालवीय, प्रवीण साहू अपनी अपनी धर्म पंथियों



के लिए टिकट मंगेगे तो वही गायत्री साहू सुधा श्रीवास भी दावेदार है परंतु टिकट का सारा दारोमदार क्षेत्र के विधायक ठाकुर विजय पाल सिंह पर निर्भर है वह जिसे चाहेंगे उसे टिकट मिलेगी दूसरी ओर नगर में सबसे मजबूत दावेदार शशि सतोष मालवीय है तो वहीं आलोक जयसवाल जगदीश भावसार जमील खान अजीज खान भी अपनी धर्म पंथियों के लिए मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेंगे सूत्रों के अनुसार सतोष मालवीय एवं शशि मालवीय अलग-अलग 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे वहीं इंदिरा वार्ड के पार्षद धर्मदास बेलवंशी और उनकी पत्नी

भी 2 वार्ड से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस की रणनीति साफ है अधिक पार्षद होंगे तो आसानी से उनका अध्यक्ष बन जाएगा परंतु भाजपा को कांग्रेस की गुटबाजी के चलते लाभ हो सकता है वहीं सत्ताधारी दल भा जा पा के कार्यकाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा आम नागरिकों को आशंका है यदि भाजपा की परिषद बन गई तब वार्ड के अंदर तक के अतिक्रमण तोड़ दिए जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत अतिक्रमण तो सब जगह हुआ है इससे विपरीत भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अतिक्रमण

टूटने से आम नागरिकों को कोई लेना देना नहीं नगर सुंदर बन रहा है इससे भाजपा को फायदा होगा खैर यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कौन-कौन मैदान में होगा और किसी टिकट मिलेगी यह 11 जुलाई से नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा 18 जुलाई को फार्म वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी दोनों ही दल के दावेदारों ने शतरंज की तरह अपनी रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिया कौन सफल होता यह भविष्य के गर्त में है।

उतारे गए बैनर पोस्टर : आचार संहिता लगते ही नगर परिषद के कर्मचारियों ने आर आई संजय परसाई के नेतृत्व में नगर के विभिन्न चौक चौराहों सहित बिल्डिंग विद्युत पोल शासकीय कार्यालय पर लगे बैनर पोस्टर उतार दिए वही दीवारों पर पुताई भी प्रारंभ कर दी है आदर्श आचार संहिता का पालन कराने प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासनिक दल कार्यवाही करता नजर आया।

तम्बाकू निषेध जागरुकता रथ ने धार व तिरला को किया जागरुक



धार / नवप्रदेश। तंबाकू जानलेवा है। हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग जान की परवाह किए बिना तंबाकू खाते हैं। यह बहुत अश्चर्यजनक है तंबाकू जीवन ही नहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक है अतः तंबाकू से दूरी बहुत जरूरी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भोज शोध संस्थान मध्य प्रदेश वालंटरी हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, मध्यप्रदेश शासन के प्रयासों से धार व तिरला में भी तंबाकू निषेध जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर विशेष रूप से जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिरीष रघुवंशी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ एम एल मालवीय, जिला तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉ संजय भंडारी व भोज शोध संस्थान के निदेशक डॉ दीपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

ली शपथ : इस महत्वपूर्ण दिन उपस्थित अतिथियों व नागरिकों ने स्वयं भी तम्बाकू ना खाने व अपने साथियों को भी तम्बाकू ना खाने व पीने की देने की शपथ ली। शपथ का वाचन डॉ दीपेंद्र शर्मा ने किया।

रथ निकला : जागरूकता रथ को रवाना करने के पूर्व हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया । इस आयोजन में म प्र शासन स्वास्थ्य विभाग(राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) व मध्यप्रदेश वालंटरी हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा तम्बाकू से शरीर व पर्यावरण को होने वाले नुकसान व तत्सम्बन्धी कानून को दशाति पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिला अस्पताल परिसर से निकला यह रथ धार नगर में घूम घूम कर जिन्यद्गी चुनो तम्बाकू नहीं, भाइयों व बहनों तम्बाकू को ना कहना, बीड़ीं सिमोरेत तम्बाकू का खतरा उग्र चाहे सत्तर हो या सत्रह जैसे संदेश प्रसारित करेगा। दूसरे दिन तिरला, आमखेड़ा व ज्ञानपुरा में भी जागरूकता फैलाई। यह जानकारी मीडियां प्रभारी राकी मकड़ ने दी।

पार्टी से युवाओं को जोड़ने का चलाया अभियान

बालाघाट। भाजपा के युवा जोड़ों अभियान के तहत शहर के सभी वार्डों में बैठक का दौरा चल रहा है। इसी कड़ी में गत दिवस शहर के वार्ड नंबर 28 में युवा जोड़ों अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक चौहान और युवा जोड़ों अभियान के जिला प्रभारी सत्येंद्र पटवा भी शामिल हुए। वहीं एक दिन पूर्व वार्ड नंबर 33 में भाजयुमो नगर महामंत्री दीपक लिहारे के नेतृत्व में 30 युवाओं ने भाजपा की रीति-नीति की शपथ लेकर सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेंद्र कटरे, जिला महामंत्री गौरव श्रीवास्तव, युवा जोड़ों अभियान के जिला संयोजक रमाकांत डहाके, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष योगराज टेम्भरे, भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी रोमेश सोनवाने, नगर महामंत्री संजू वराडे, नगर उपाध्यक्ष सिद्धार्थ वाजपई, नगर मंत्री आनंद पिछोड़े, नगर मंत्री रंजीत गोयल आदि युवाओं का भाजपा का गमछा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई।



कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के साथ किया छलावा : संजय राय

राजगढ़/ नवप्रदेश।। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक देश पर शासन किया लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं किया ना ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई। मप्र के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह ने पंचायत एवं निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कोर्ट में सरकार की जीत भी हुई। उक्त बात गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए



पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कही उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग की महत्व पूर्ण भूमिका है सभी कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिताने। वही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के आठ वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां आमजन को बताईं। इस मौके

पर नव गठित जिला कार्यकारणी व पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश मंत्री लखन दांगी कार्यकारिणी सदस्य पूजा सोंधिया द्वारा भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री श्याम मंडलोई ने किया इस मौके पर प्रदेश कार्यलय मंत्री जितेंद्र चंद्रवंशी जिला महामंत्री भगवान दास साहू, मीडिया प्रभारी मैच नामदेव तथा जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी सभी मंडल अध्यक्ष महामंत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राहत राशि वितरण में किये गये घोटाले के दोषियों पर अभी तक नहीं हुई कार्यवाही

जिनके कार्यकाल में हुआ घोटाला, उन्ही को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

सिलवानी / नवप्रदेश। वर्ष 2020-21 में कीट व्याधी, ओलावृष्टि, किसानो की फसलो के हुये नुकसान को लेकर राहत राशि वितरण में किये गये घोटाले की जांच की मांग को पिछले पखवाड़े मे बजरंग चैराहे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामजीलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की थी। कलेक्टर उक्त प्रकरण की जांच के लिए एक दल घटित कर जांच कराई जा रही है। सवाल यह उठता है सिलवानी के तत्कालीन तहसीलदार ब्रजेशसिंह को जांच दल का प्रभारी बनाया जा। जबकि उनके कार्यकाल के दौरान उक्त घोटाला हुआ था। अब जांच किस स्तर की होगी विचारणीय पहलू है। कलेक्टर अरविन्दकुमार दुबे द्वारा बनाये गये जांच दल में ब्रजेश सिंह तहसीलदार, एवं सिलवानी तहसील में ही पदस्थ राजस्व निरीक्षक, तथा पटवारीयों को जांच दल में नियुक्त किया गया है। इस बात से सहज ही अनुमान

लगाया जा सकता है। यह जांच दल किस तरह की जांच करेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहनसिंह रघुवंशी, भरत पटेल, कृष्णकुमार का कहना है कि प्रशासन को अन्य तहसील का स्वतंत्र दल जांच हेतु गठित करना था। जोकि सभी पहलुओं की जांच करता परंतु प्रशासन द्वारा सिलवानी के ही अधिकारी कर्मचारियों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है जो कि व्यावहारिक नहीं है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने ज्ञापन में मांग की थी कि वर्ष 2020-21 में कीट व्याधी, ओलावृष्टि, किसानो की फसलो के हुये नुकसान को लेकर सरकार द्वारा लगभग 18 करोड़ की राशि स्वीकृत किया किसानो को राशि वितरण किया जाना थी लेकिन पटवारी शशांक दुबे एवं अन्य पटवारीयो द्वारा बड़े पैमाने पर किसानो को मिलने वाली राहत राशि में घोटाला किया गया है किसानो के कुछ सूचियों में नाम सही लिखे हैं, कुछ सूचियों में नाम, रकवा तथा ग्राम सही लिखे है लेकिन खाता नम्बर

एवं आई.एफ.सी. कोड अन्य लोगो के है जो इस तहसील के निवासी नहीं है, वहीं दूसरी ओर कुछ किसानो के फज्जी नाम राहत राशि सूची में जोड़कर अनेको बैंको के खातो में किसानो को मिलने वाली राहत राशि डालकर, पटवारी एवं अधिकारीयो से साठ-गाठ करके मिली भागत से करोड़ों रूपयों का घोटाला किया गया है। वहीं कुछ किसानों को राहत राशि तो मिली है परन्तु पूरी राशि किसानो को नहीं मिली है। पटवारियों के साथ सिलवानी ट्रेजरी प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध है। पटवारी हल्का जुनिया, नीगरी, बन्हौरी-वर्धा, आदि सहित अन्य हल्कों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार करके घोटाला किया गया है। इन सभी की राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय टीम गठित कर 01 सप्ताह के अंदर जांच कराकर, जांच में दोषी पाये जाने पर कर्मचारी एवं अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग की गई थी।

‘कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने चुनाव संबंधी तैयारियों का लिया जायजा, आचार संहिता का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

झाबुआ। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह के द्वारा दिनांक 01 जून, को सायं कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्देश दिए की आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से अध्ययन कर ले एवं सक्ति से पालन कराए। गंभीर रूप से कोई बीमार को और मुख्यमंत्री सहायता कोष से ईलाज की आवश्यकता हो तो ऐसे प्रकरण बनाकर भेजे जाए अनुमति दी जाएगी। नए निर्माण कार्य अब शुरू नहीं होने चुनाव निष्पक्षता के साथ हो इसके लिए सभी व्यवस्था की जाए। नामांकन ऑफलाइन और ऑन लाइन भरे जा सकते है। पार्षद के लिए पहली बार व्यय सीमा तय की गई है। चुनाव होने के तीन दिन के भीतर व्यय लेखा जरूर ले। स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उन क्षेत्रों में एक साथ भ्रमण करें। यहां मतदान प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस बैठक में झाबुआ से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अरविन्द्र तिवारी, अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाव्दा, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिल झा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एत.एन.गर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी

संक्षिप्त समाचार

जिला सड़क सुरक्षा समिति के गठन में संशोधन

धार ।कलेक्टर डॉ फंजक जैन ने पूर्व में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति के गठन में संशोधन किए जाने का आदेश जारी किया है। संशोधित गठित समिति अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी समिति के अध्यक्ष है। जबकि पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीजनल ऑफिस मार्ट एंड एच, परियोजना संचालक एन एच ए आई ईकाई, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सचिव लायंस क्लब, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इस समिति में सदस्य बनाए गए हैं तथा महाप्रबंधक एमपीआरडीसी इस समिति में सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

मतदान दलों से संबंधित निर्देश हुए जारी

धार ।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को सम्पन्न कराए जाने हेतु मतदानकर्मियों के संबंध में आवश्यक दायित्व संबंधी दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है जिसमें कड़िका नम्बर नौ में उल्लेखित है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह या उससे कम समय अवधि शेष हो इस प्रकार के सभी कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। इस प्रकार के कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराए जा सकते है।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन - 2022 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने रानापुर विकासखण्ड की व्यवस्थाओं का लिया जायजा



झाबुआ। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन - 2022 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी के द्वारा रानापुर में स्थापित निर्वाचन स्ट्रॉग रूम का आंतरिक एवं बाहरी अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त निर्वाचन के दौरान जहां पर बसों एवं वाहनों की पार्किंग आदि के लिए मैदान का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं आदर्श आवरण संहिता के परिपालन में विकास खण्ड रानापुर में निर्वाचन व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने के लिए विकासखण्ड स्तरीय व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिसमें आज विकासखण्ड रानापुर के स्ट्रॉग रूम की व्यवस्था का संयुक्त रूप से अवलोकन किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। यहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस प्रशासन के अमले को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ एत.एन.गर्ग, इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग विजयसिंह पंवार एवं एसडीओ डीके शुक्ला, तहसीलदार रानापुर सुखदेव डावर, एसडीओ लोक निर्माण विभाग डीके शुक्ला, सीईओ जनपद पंचायत जी.एस.मुजाव्दा एवं धाना प्रभारी रानापुर भी इस दौरान उपस्थित थे।

आर्वी बिसेन ने जिले का नाम किया रोशन, अमेरिका की कंपनी ने दिया 1 करोड़ 24 लाख का पैकेज

बालाघाट। बालाघाट शहर के जाने-माने निवासी स्व. डॉ. मेघराज बिसेन के सुपुत्र अशोक बिसेन की पुत्री क. आर्वी बिसेन ने अमेरिका के बफैलो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त की है एवं आर्वी का चयन अमेरिकन फरम सोलोमन मे सिनियर पोजिशन पर हुआ है। वह अपनी सेवाये न्यूयॉर्क में देगी। आर्वी को इस हेतु 01 करोड़ 25 लाख रु. का सालाना पैकेज अमेरिकन कंपनी प्रदान करेगी। ज्ञात हो कि आर्वी के पिता नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में पी. जी. टी के पद पर पदस्थ है जिनका पेटुक्त ग्राम-पोंडी (उकवा) है। आर्वी डॉ. भीमराज बिसेन बालाघाट की भतीजी हैं। आर्वी की इस सफलता पर समस्त परिवारजन गौरवावित है एवं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है।

सुलियरी कोल ब्लॉक के वाहनों को विस्थापितों ने रोका

पहले विस्थापन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया पूर्ण करने की उठाई मांग

सिंगरीली/ नवप्रदेश।

।एपीएमडीसी एण्ड अदानी कोल ब्लॉक का मामला फिर से गरमाने लगा है। विस्थापितों ने कंपनी के खिलाफ हल्ल बोल दिया है। अभी बीते दिवस अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। वहीं बुधवार को विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन के दौरान सुलियरी कोल ब्लॉक से हो रहे कोल उत्खनन व परिवहन पर रोक लगा दिए हैं। जब तक विस्थापन नीति की कार्यवाई पूर्ण नहीं होगी तब तक कंपनी का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। विस्थापितों का मोर्चा देख प्रशासन भी हकत में आया जहां सरई थाना प्रभारी नेहरु सिंह खण्डते के साथ-साथ लंघाडोल थाना प्रभारी बालेन्द्र त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। इधर बताते चले कि सुलियरी कोल ब्लॉक के विस्थापितों का आरोप है कि पूर्व में जो धरना प्रदर्शन कंपनी के खिलाफ विस्थापितों ने किया था उस दौरान कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कंपनी के द्वारा किसी भी विस्थापित के



साथ अन्याय नहीं होगा। विस्थापन नीति का पालन करते हुए कंपनी अपना कार्य प्रारंभ करेगी। लेकिन प्रशासन भी कंपनी के ही इशारे पर चल रहा है। इस तरह के आरोप विस्थापितों ने प्रशासन पर लगाया है। वहीं तक्रोबन एक सप्ताह से सुलियरी कोल ब्लॉक व अदानी के क्रियाकलापों से परेशान होकर विस्थापितों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा था कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विस्थापितों के ज्ञापन का कोई असर प्रशासन व कंपनी पर पड़ता

हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके चलते विस्थापितों ने कंपनी के तानाशाही रवैये से त्रस्त होकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं।

कोल वाहनों के रुके पहिए

सुलियरी कोल ब्लॉक के विस्थापितों ने अा रुप दिखाते हुए सुबह से ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के दौरान सुलियरी कोल ब्लॉक से कोल परिवहन करने वाले वाहनों को रोक दिया गया। इस कदर विस्थापितों ने हुंकार भरी थी कि कंपनी प्रबंधक मजबूर हो गया।

बताया जाता है कि कोल परिवहन पूरी तरीके से बंद था। विस्थापितों ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक कंपनी को तत्काल कंपनी के द्वारा हटया जाए। क्योंकि शैलेन्द्र सिंह के द्वारा विस्थापितों के साथ हमेशा से दुर्व्यहार किया गया है। आज विस्थापितों को जो स्थिति निर्मित है कहीं न कहीं शैलेन्द्र सिंह का हाथ है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल एपीएमडीसी हटाए नहीं तो विस्थापित कुछ भी करने को बाध्य हो जाएंगे।

एपीएमडीसी से शैलेन्द्र सिंह को हटाया जाए

सुलियरी कोल ब्लॉक के विस्थापितों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एपीएमडीसी कंपनी में कार्य करने वाले शैलेन्द्र सिंह को तत्काल कंपनी के द्वारा हटया जाए। क्योंकि शैलेन्द्र सिंह के द्वारा विस्थापितों के साथ हमेशा से दुर्व्यहार किया गया है। आज विस्थापितों को जो स्थिति निर्मित है कहीं न कहीं शैलेन्द्र सिंह का हाथ है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल एपीएमडीसी हटाए नहीं तो विस्थापित कुछ भी करने को बाध्य हो जाएंगे।

